

ट्रम्प का फोटो

साधारण अपराधी के तौर पर लिया गया यह "मग शॉट" ट्रम्प की उग्र मुद्रा के कारण वायरल हो गया है

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 अगस्त। एक साधारण सा "मगशॉट" अमेरिका में भारी विवाद पैदा कर रहा है। जेल जाने वाले अपराधियों को तस्वीर खिंची जाती है उसे "मगशॉट" कहते हैं। इस मामले में तस्वीर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की है जिन्होंने अपने विरुद्ध चल रहे 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हेराफेरी करने के अपराधिक मुकदमे में जॉर्जिया के जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। चुनाव में हेराफेरी और जनादेश को प्रभावित करने का प्रयास अमेरिका में गंभीर अपराध माना जाता है और इसीलिए अमेरिका की विधिािका ने ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है।

भारतीय मतदाताओं का अनुभव देखते हुए, जैसा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में हुआ है, यह सोचना पड़ता है कि क्या हमारे देश में भी चुनाव प्रक्रिया में छेड़छाड़ करने के लिए ऐसी कड़ी सजा आवश्यक है। इससे दर्जनों मौतों और खून खराबा रोका जा सकता है।

डॉनल्ड ट्रम्प ने जहां फुल्टन काउंटी अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया वहां जॉर्जिया की जेलबुक निर्देशिका में आवश्यक है कि सभी कैदियों के फोटो खिंचे जाने चाहिए- इस मामले में अपराधी के चेहरे का एक सामान्य फोटो होता है जिस पर जेल अधिकारियों की मुहर लगी होती है। जिस व्यक्ति का कभी अमेरिका के परमाणु बदन पर नियंत्रण था, जो अमेरिकी सेनाओं का प्रमुख था और कथित रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहा था, उसके लिए



यह भारी अपमान था। ऐसा व्यक्ति भी अपने प्रायश्चित्त पर नियंत्रण नहीं कर पाया और उसे एक साधारण कैदी की तरह फोटो खिंचवानी पड़ी। डॉनल्ड ट्रम्प को एक कैदी नंबर भी आवंटित किया गया। मगशॉट में ट्रम्प का चेहरा कदापि सामान्य नहीं लग रहा है। वे कैमरे में धमकी भरे अंदाज में देख रहे हैं, उनकी नजर में धमकी नजर आ रही है। फोटोग्राफ में उनका चेहरा अवज्ञाकारी दिख रहा है, वे दुर्दृष्टिपूर्ण तथा परेशान करने वाला व्यक्ति दिखाई देने का अतिरिक्त प्रयास करते नजर आ रहे हैं।

जाहिर है, यह सब बना हुआ था। अभियोग चलाया जाना उसके बाद, एक सामान्य अपराधी की तरह जेल जाना किसी पूर्व राष्ट्रपति के लिये कोई मोहक नियात नहीं है। इसके अलावा, जॉर्जिया राज्य में, ट्रम्प पर अपराधिक घडयंत्र तथा "इरादतन अपराधिक कृत्य" में शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है।

इसे आर.आई.सी.ओ. अधिनियम कहा जाता है तथा अमेरिका में क्रिमिनल माफिया से निबटने के लिये तैयार किया

विशेषज्ञों का कहना है कि, अपनी इस गुस्से भरी मुद्रा से ट्रम्प यह दिखाना चाहते हैं कि, वे डरे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है।

ट्रम्प समर्थकों ने इस तस्वीर को टी शर्ट्स और कॉफी मग आदि पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है।

ट्रम्प ने, चुनावों में फर्जीवाड़े के मामले में आज जॉर्जिया में आत्मसमर्पण किया। यहाँ जेल में उनकी साधारण कैदी की तरह तस्वीर खिंची गई। हालांकि ट्रम्प जल्दी ही रिहा हो गए।

गया था। अमेरिका में अपराधिक इरादे वाले किसी अपराधिक गुप्त से किसी भी किस्म का जुड़ाव भी आर.आई.सी.ओ. अधिनियम के तहत, एक दंडनीय अपराध है। कोई आदमी सीधे ही अपराध न भी कर रहा हो, अपराध करने वालों के साथ उसका किसी भी किस्म का जुड़ाव पर भी सजा मिल सकती है।

मानो, अभियोजकों के प्रति बाजी पलटते हुये, डॉनल्ड ट्रम्प ने मगशॉट में स्वयं को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वे ताकत और प्रतिशोध का भाव व्यक्त कर रहे हैं। पूरी तरह प्रतिकूल स्थिति में एक तरह से ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रम्प के चुनाव कार्यालय ने यह प्रोजेक्ट करने के लिये जेल में मगशॉट का उपयोग किया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। ट्रम्प हमेशा की तरह जॉर्जिया स्टेट के अभियोजकों पर जमकर बरसे हैं, जो अश्वेत हैं तथा ट्रम्प स्वयं को श्रेष्ठ श्वेत वर्ग के पक्षकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

डॉनल्ड ट्रम्प कितने भी अधम हों, उन्होंने यह मगशॉट सोशल मीडिया में, खासतौर से पूर्ववर्ती ट्विटर प्लेटफॉर्म

को टी शर्ट्स तथा कॉफी मग जैसे अन्य चीजों में बिन्नी के लिये रख दिया है। लेकिन अमेरिकन बुद्धिजीवी तथा अधिजात्य वर्ग, चाहे वह रिपब्लिकन पार्टी का ही क्यों न हो, इस तथ्य से नहीं बच सकता कि एक पूर्व राष्ट्रपति जिसने देश भर में 91 अपराधिक आरोपों का सामना किया है, उसे उन्हीं जिले के अधिकारियों के समक्ष समर्पण करना पड़ा है।

यद्यपि कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि ट्रम्प का स्वयं को एक ऐसे पंडित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है जिसने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये प्रयास जनता को, उनकी पार्टी तथा आरोप लगाने वालों को प्रभावित कर सकते हैं।

ट्रम्प आख्यान, पर सबसे सटीक बात यह है कि उन्हें एक सामान्य अपराधी की तरह फोटो खिंचवानी पड़ी। उक्त आलोचक ने ट्रम्प के मगशॉट पर कहा, एक ऐसा चेहरा, जिसे सारी दुनिया जानती है, अपकीर्ति में जम गया है। अमेरिका का शोकजनक एक युग कैमरे की एक क्लिक में कैद हो गया।

पुतिन भारत नहीं आएंगे

माँस्को, 25 अगस्त। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत नहीं जाएंगे। रूसी राष्ट्रपति के

रूस के राष्ट्रपति जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने वाले थे।

प्रवक्ता दिमित्रि पेस्कोव ने शुक्रवार का यहां मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, पुतिन भारत में सितंबर में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन के लिए यात्रा की योजना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि, इस समय मुख्य जोर विशेष सैन्य अभियान पर है। जी-20 शिखर सम्मेलन नौ और 10 सितंबर को नयी दिल्ली में प्रगति मैदान में नवनिर्मित भारत मंडपन में आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि, पुतिन दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में संपन्न हुए ब्रिक्स के 15 वें शिखर-सम्मेलन में भी भाग लेने नहीं गए थे।

राहुल गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कारगिल युद्ध के सभी वीर सेनानियों और शहीदों को मेरा शत शत नमना" कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर लड़ाख के लोगों को अनेदखी का आरोप लगाते हुए कहा, "भारत जोड़ी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी लड़ाख के लोगों से मिले। यात्रा की भावना के अनुरूप उन्होंने उनकी मन की बातें सुनीं। इन समस्याओं को सुनकर स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार ने लड़ाख को उसके हाल पर छोड़ दिया है। जिन नेताओं को केवल अपने मन की बात में दिलचस्पी है, वे कभी भी जनता की आवाज को सुनने नहीं देंगे।"

जोहैनसबर्ग में मोदी ने विमान से उतरने से मना कर दिया था

दक्षिण अफ्रीका की न्यूज साइट डेली मैवरिक ने दावा किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 अगस्त। गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के 15वें सम्मेलन के दौरान किसकी पहल पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई, से लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो गया है क्योंकि दोनों पक्ष दावे और प्रतिदावे पेश कर रहे हैं।

चीन ने अधिकारिक रूप से कहा है कि दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक भारत के निवेदन पर हुई जबकि भारतीय आधिकारिक सूत्रों ने अनौपचारिक रूप से कहा, "चीन की ओर से द्विपक्षीय बैठक का निवेदन काफी समय से लंबित है। सूत्रों ने कहा कि दोनों नेताओं की जोहैनसबर्ग में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान लीडर्स टालेंज में "अनौपचारिक बातों" हुई।

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, "राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवेदन पर वार्ता की।" बैठक में दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तेजी से तनाव घटाएँ क्योंकि वहां जून 2020 से तनाव चल रहा है जब लड़ाख की गलवान घाटी में दोनों पक्ष टकराए थे। दोनों नेता अपने देशों में कार्मिकों को यह निर्देश देने के लिए सहमत हुए कि एल.ए.सी. पर सेना कम की जाए।

भारत के विदेश सचिव विनय खन्ना ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, "यह ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता थी। प्रधानमंत्री ने अन्य ब्रिक्स नेताओं से भी विचार-विमर्श किया। जिनपिंग के साथ वार्ता में प्रधानमंत्री ने एल.ए.सी. तथा भारत-चीन सीमा के अन्य क्षेत्रों के अनुसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंता व्यक्त की।" क्वाना ने कहा, "इस मामले में दोनों नेता सहमत हो गए कि वे संबंधित अधिकारियों को तनाव जल्द से जल्द घटाने के लिए निर्देश देंगे।

चीन की एक विज्ञापित वेबसाइट ने अनुसार दोनों नेताओं के बीच वर्तमान भारत-चीन संबंधों तथा और अन्य साझा हित के मुद्दों पर निष्कर्ष और गहराई से विचार-विमर्श हुआ। चीन के वक्तव्य के अनुसार राष्ट्रपति शी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-चीन संबंधों में सुधार से दोनों देशों और उनकी जनता के साझा हित पूरे होंगे, विश्व तथा क्षेत्र में शांति, स्थायित्व एवं विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

चीन के विदेश मंत्रालय ने शी के हवाले से कहा, "दोनों पक्षों को आपसी संबंधों के समग्र हित ध्यान

न्यूज साइट ने कहा कि, मोदी के स्वागत के लिए एक कैबिनेट मंत्री भेजा गया था इसलिए मोदी ने विमान से उतरने से मना कर दिया था।

न्यूज साइट ने आगे कहा कि, बाद में उपराष्ट्रपति जरूरी मीटिंग छोड़कर स्वागत आते एब प्र.मंत्री मोदी ने जोहैनसबर्ग में कदम रखा।

में रखने चाहिए और सीमा-विवाद का ढंग से हल निकाला जाना चाहिए ताकि सीमा क्षेत्र में संयुक्त रूप से शांति स्थापित की जा सके।" वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव के बाद यह मोदी और शी के बीच पहली मुलाकात थी। दोनों देशों ने सीमा विवाद हल करने के लिए सेना स्तर की वार्ताओं की हैं।

दोनों सेनाओं ने हाल ही में कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 19वां दौर किया। विदेश मंत्रालय के एक वक्तव्य के अनुसार, "वे बकाया मुद्दों को जल्दी हल करने और सैन्य तथा कूटनीतिक माध्यमों से वार्ता जारी रखने पर सहमत हुए। इस दरम्यान दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर सहमति जताई।" दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पिछले कई दशकों से जारी है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध भी हुआ था।

ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए मोदी की साउथ अफ्रीका यात्रा विवादों के घेरे में रही क्योंकि जोहैनसबर्ग में उनका आगमन प्रदर्शनों के घेरे में आ गया जब दक्षिण अफ्रीका की एक समाचार वेबसाइट डेली मैवरिक ने खबर दी कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त को विमान से उतरने से मना कर दिया क्योंकि मेजबान सरकार ने उनकी अगवानी

के लिए किसी वरिष्ठ अर्थोर्टी को नहीं भेजा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मैशालाइट के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी हमेशा से ही मोदी का स्वागत करने की योजना थी। प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विमान उतरने से काफी पहली मैशालाइट प्रेसोविया के वाटरक्लफ हवाई अड्डे पर मौजूद थे जो जोहैनसबर्ग के निकट है जहाँ ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। दूसरी ओर डेली मैवरिक ने कहा कि आरंभ में एक कैबिनेट मंत्री को वाटरक्लफ हवाई अड्डे भेजा गया था भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने, लेकिन मोदी ने विमान से उतरने से इंकार कर दिया।

वैबसाइट ने कहा, "इसके विपरीत राष्ट्रपति सीरियल रामाफोसा सोमवार की रात को पहुंचने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अगवानी में स्वयं पहुंचे।" वैबसाइट ने कहा कि अधिकारियों का आरोप है कि अंततः उपराष्ट्रपति पॉल मैशालाइट शी के लिए आयोजित एक कार्यक्रम बीच में छोड़कर वाटरक्लफ हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी करने पहुंचे।" यह कहा जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका की राजकीय यात्रा पर हैं जिसका अलग प्रोटोकॉल है और मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में गए हैं जिसका प्रोटोकॉल अलग है।

भारत-पाक सीमा पर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(माइन) नजर आई, जिसने ग्रामीणों को और ग्रामीणों ने सीमा सुरक्षा बल को इसकी सूचना दी। सीमा सुरक्षा बल की टीम ने लैण्डमाइन की पड़ताल की। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने झिनझिनयाली पुलिस को इसकी सूचना दी।

झिनझिनयाली थाना प्रभारी हड़वंत सिंह ने बताया, "सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने जिंदा एंटी पर्सनल माइन की जानकारी दी। जिसके बाद हमने म्याजलार पुलिस चौकी को इतला देकर मौके के लिए रवाना कर दिया।" थाना प्रभारी ने बताया कि, भारतीय सेना के कंट्रोल रूम को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। अब सेना का इम निरोधक दस्ता मौके पर आया और वो ही इसे डिफ्यूज करने की कार्यवाही करेगा। तब तक एंटी पर्सनल लैण्डमाइन हमारे कब्जे में रहेगी।

कहा जा रहा है कि, भारतीय सेना के किसी युद्धाभ्यास में ये जमीन में ही दबी रह गई और आंधी चलने से जब रेत उड़ी तो यह जमीन से बाहर आ गई। एंटी पर्सनल माइन का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ किया जाता है, जबकि एंटी-टैंक माइन का इस्तेमाल भारी गाड़ियों के लिए किया जाता है। ये माइन्स घुसपैठियों और दुश्मन की पैदल सेना के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम करते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और बड़ी संख्या में तैनात किये जा सकते हैं और सीमाओं पर दुश्मन सैनिकों को मार गिराने के लिए जमीन में दबाए जाते हैं। पैर पड़ते ही माइन धमाके के साथ फटती हैं और दुश्मन सैनिक के परखच्चे उड़ा देती है।

बिहार में जात आधारित गणना का काम पूरा : नीतीश

पटना, 25 अगस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि, प्रदेश में जाति आधारित गणना का काम पूरा हो चुका है और आंकड़ा तैयार हो जाने के बाद रिपोर्ट की घोषणा कर दी जाएगी।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा करत हुए कहा कि, गणना का आंकड़ा तैयार किया जा रहा है, जब सबकुछ तैयार हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट घोषित की जाएगी।

नीतीश कुमार ने शुक्रवार को यहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बी. पी. मंडल की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि देने के बाद संबदादाताओं से बातचीत में कहा कि, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, अब उसके आगे एक-एक चीज को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि, आंकड़ा तैयार किया जा रहा है, जब सबकुछ तैयार हो जाएगा तो फिर रिपोर्ट घोषित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही जाति आधारित गणना का सारा काम हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने भी सर्वे के काम को रोका नहीं है। इस सर्वे में मुख्य बात है कि, सबकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल जाएगा। केवल जातियों की संख्या घोषित करने के लिए यह

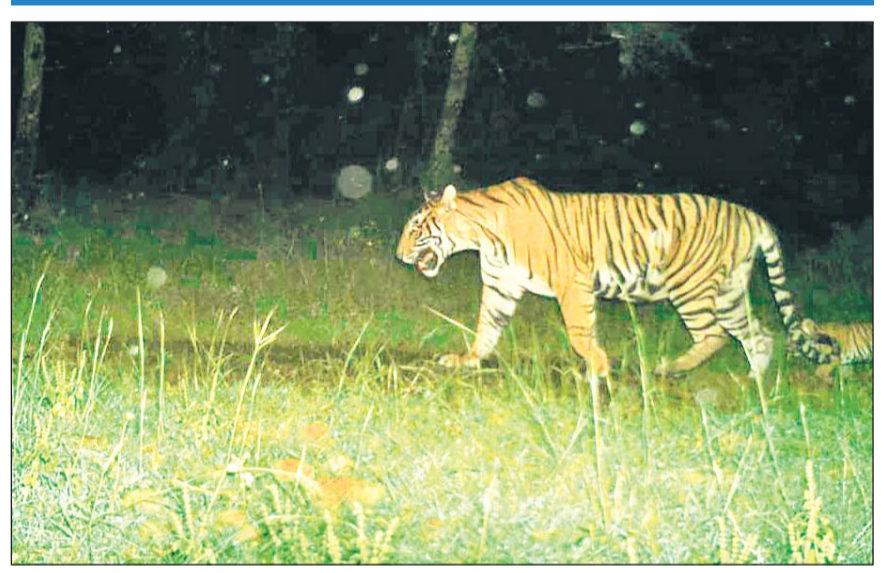
सर्वे नहीं करवाया जा रहा है। सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही हैं। वर्ष 2021 में ही सभी पार्टियों की सहमति से जाति आधारित गणना का कार्यक्रम तय किया गया था। सब कुछ तय होने के बाद वर्ष 2022 में सर्वे का काम शुरू हो गया था।

कुमार ने कहा कि, देश में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता था। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में जाति आधारित जनगणना भी करायी गयी थी लेकिन फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। आज वर्ष 2021 के बाद कितने साल बीत गए लेकिन जनगणना का काम नहीं हुआ है। कुछ लोग देश का इतिहास बदलने में लगे हुए हैं। जो जरूरी काम है वो नहीं हो रहा। किसकी कितनी आबादी है और किसको कितना लाभ दिया जाएगा, ये सब जरूरी है जो नहीं किया जा रहा है। जब बिहार में जाति आधारित गणना का काम हो जाएगा तो अन्य राज्य के लोग भी इसको देखेंगे। कई राज्य अपने स्तर से जाति आधारित गणना कराना चाहते हैं। बिहार इसका एक मॉडल बनेगा। ये काम सबके हित में होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, उनकी आबादी कितनी है और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, जाति आधारित गणना से ये सारा कुछ पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कोई गांव में रहता था लेकिन अब अगर वो दूसरी जगह चला गया है तो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, सर्वे करने वाले को ये सब अध्ययन करके रिपोर्ट देनी है। इसी से सभी जातियों की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा।

रणथम्भौर में बाघिन टी-107 ने शावकों को जन्म दिया

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में 81 बाघ-बाघिन व शावक हैं



सवाईमाधोपुर, 25 अगस्त (निर्स)। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व से एक बार फिर से खुशखबरी आई है। यहां इस बार बाघिन टी-107 सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया है, जिससे चलते वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

रणथम्भौर टाइगर रिजर्व प्रथम के मोहित गुला ने बताया कि रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की रेंज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर में टी-107 की शावकों को जन्म देने की संभावना थी। इसलिए बाघिन की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। शुक्रवार को रेंज के नाका शेरपुर में

शुक्रवार को काली तलाई के पास बाघिन टी-107, जिसका नाम सुल्ताना है, एक शावक के साथ कैमरा ट्रैप में देखी गई है। सुल्ताना की उम्र सात वर्ष है और वह बाघिन टी-39 की बेटी है।

काली तलाई के पास बाघिन टी-107 एक शावक के साथ कैमरा ट्रैप में कैद हुई है। वनाधिकारियों के अनुसार

बाघिन के एक से ज्यादा शावक होने की संभावना है। बाघिन टी-107 की उम्र 7 साल है और यह बाघिन टी-39 की बेटी है।

बाघिन टी-107 ने तीसरी बार शावक को जन्म दिया है। इससे पहले यह दो बार प्रजनन कर चुकी है। फिलहाल वनाधिकारियों की ओर से फील्ड स्टफ को सुरक्षा व मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि रणथम्भौर में जुलाई में बाघिन टी-84 रोहेड़ो है। शावकों को जन्म दिया था। इस समय रणथम्भौर में 81 बाघ- बाघिन और शावक हैं।

विदेश से महंगा कोयला क्यों खरीद रही है गहलोत सरकार : बिहारी लाल बिश्नोई

बिकानेर, 25 (कांस)। नोखा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई ने भाजपा संभाग कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों को बिजली माफो के नाम पर जब कटाने का काम किया है। बिश्नोई ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में 23,309 मेगावाट विद्युत क्षमता के साथ राजजिन को बिजली की दृष्टि से आत्मनिर्भर करने की घोषणा करने वाली गहलोत सरकार का असली चेहरा अब सामने आ गया है।

बिश्नोई ने कहा कि देश में कोयला संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को 6 प्रतिशत तक विदेश से कोयला खरीद करने की अनुमति दे रखी है। इसकी आड में एक बार फिर गहलोत सरकार महंगा कोयला खरीद रही है। पहले राज्य सरकार ने एफ्ट के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए अडानी समूह से करीब 1042 करोड़ का 5.79 लाख मीट्रिक टन कोयला 18 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की

विदेश से 3.38 लाख मीट्रिक टन कोयला 15 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की लागत से आयात करने की तैयारी कर रही है सरकार आज भी 4 से 6 हजार रुपये मीट्रिक टन की दर से बाजार में स्वदेशी कोयला उपलब्ध है बिश्नोईने कहा कि दरों में इतना बड़ा अंतर भ्रष्टाचार का संकेत

लागत से एकल निविदा में खरीदा। अब एक बार फिर विदेश से 3.38 लाख मीट्रिक टन कोयला 15 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की लागत से आयात करने की तैयारी कर रही है। तीन हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की दरों का अंतर भ्रष्टाचार का संकेत दे रहा है। जबकि आज भी 4 से 6 हजार रुपये मीट्रिक टन की दर से बाजार में स्वदेशी कोयला उपलब्ध है। बिश्नोई ने कहा कि 6 बार बिजली की दरों में वृद्धि करने तथा साढ़े 4 वर्ष तक औसतन 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचाज वसूलने, 100 यूनिट प्रतिमाह

देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 24 अगस्त से सप्ताह के अंत तक जिला स्तर, उपखंड स्तर व जीएसएस पर विरोध प्रदर्शन करेगी तथा जीएसएस पर काले झंडे लगाकर सकेतिक धरना देगी। भाजपा युवा मोर्चा, किसान मोर्चा व महिला मोर्चा बिजली कटौती पर लालटेन टॉच मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।

बिश्नोई ने कहा कि वर्तमान में पीक ऑवर्स में बिजली की डिमांड 16500 मेगावाट तक पहुंच गई है। वहीं विद्युत उपलब्धता मात्र 13 से 14 हजार मेगावाट है। इसका सबसे बड़ा कारण सरकार की अकर्मण्यता से कोटा, सूरतगढ़, छबड़ा व कालीसिंध पावर प्लांट की 2740 मेगावाट क्षमता वाली 7 यूनिट को कोयले की कमी व तकनीकी रखरखाव के कारण बंद करना है। बिजली की कमी के बहाने सरकार महंगा बिजली खरीदकर व संस्थागत भ्रष्टाचार के घडयंत्र के कारण बिजली कटौती से आम उपभोक्ता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।

चीन कहता है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखना आवश्यक है। क्वाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी सहमत हुए कि संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे जल्द तनाव घटाने के उपाय और तेज करें। मई 2020 में पूर्वी लड़ाख की सीमा पर हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के संबंधों में काफी तनाव आ गया है। व्यापक सैन्य और कूटनीतिक प्रयासों के कारण दोनों पक्ष कई क्षेत्रों में पीछे हट गए लेकिन पूर्वी लड़ाख में कई टकराव के स्थानों पर भारतीय और चीनी सेना तीन वर्ष से ज्यादा से आमने-सामने है। सीमा विवाद सुलझाने में भारतीय और चीनी नेता कितने गंभीर हैं?

क्या इस पूरी कवायद का उद्देश्य अपने देशों में अपनी छवि फिकसित करना है? यदि पुराना अनुभव कुछ संकेत देता है तो चीन एल.ए.सी. पर वास्तविक शांति और समझौते के अपने वादों से पीछे हट चुका है। क्या वह इस कहावत को सिद्ध कर रहा है, "वादे किए ही तोड़े जाने के लिए जाते हैं।" केवल समय ही बताएगा।